Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 6, June - 2025

DOIs:10.2018/SS/202506013 --:-- Research Paper / Article / Review

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता

डॉ. दिनेश कुमार मौर्य
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, एमo एलo केo (पीo जीo) कॉलेज
बलरामपुर, उत्तर प्रदेश - 271201 (उत्तर प्रदेश)
Email - prodkmaurya@gmail.com

सारांश : नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने और छात्रों को कौशल विकास प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना है। आजकल, कौशल-आधारित शिक्षा की अत्यधिक प्रासंगिकता है क्योंकि यह छात्रों को नौकरी के बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है। जॉन डेवी का मानना है "शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा स्वयं जीवन है।" दरअसल शिक्षा हासिल करते हुये मनुष्य अवगुणों को त्याग रहा होता है व सद्गुणों को आमंत्रित कर रहा होता है। इस प्रक्रिया में खामियाँ दूर हो रही होती हैं और मनुष्य खूबियों से लद रहा होता है। जीवन के असल आनंद की अनुभूति शिक्षा से ही हो रही होती है बशर्ते शिक्षा के उद्देश्यों में तथ्यों का नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का समावेश हो। किताब, कागज़, स्याही, चॉक, ब्लैकबोर्ड और शिक्षक से आगे निकलकर शिक्षा कंप्यूटर व प्रोजेक्टर यानी ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम में प्रवेश कर चुकी है। भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट 'आइरिस' केरल के विद्यालय में लांच हो चुका है। यह दौर शिक्षा के लिए संभावनाओं व चुनौतियों का दौर है। यदि विद्यार्थी और शिक्षक इस दौर में संभलते हुये क़दम न बढ़ाएंगे तो शिक्षा के असल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पायेगा। इसलिए इस दौर में शिक्षक की भूमिका पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, और विद्यार्थियों के कर्तव्य बढ़ जाते हैं। "बुद्धिमत्ता और चरित्र का सही विकास सच्ची शिक्षा का मूल लक्ष्य है।"

मुख्य शब्द : पाठयक्रम, प्रौद्योगिकी, शिक्षण विधि, व्यावसायिक शिक्षा |

1. प्रस्तावना :

व्यावसायिक शिक्षा, जिसे कौशल विकास शिक्षा भी कहा जाता है, छात्रों को विशिष्ट व्यवसायों या नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। यह शिक्षा पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से अलग होती है, और विशिष्ट उद्योगों या व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करती है. व्यावसायिक शिक्षा व्यापक प्रकृति की है। सामान्य शिक्षा के अलावा, यह आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के अधिग्रहण को भी प्रोत्साहित करती है। यह सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सतत शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों को एक कुशल शिल्प के लिए तैयार करती है । व्यावसायिक शिक्षा को उस प्रकार की शिक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है जो किसी व्यक्ति को आवश्यक कौशल के साथ लाभकारी रूप से नियोजित या स्वरोजगार

के लिए तैयार करने के लिए दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा को संबंधित देश के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें करियर और तकनीकी शिक्षा शामिल है , या टीवीईटी (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण; यूनेस्को द्वारा उपयोग किया जाता है) और टीएएफई (तकनीकी और आगे की शिक्षा) जैसे संक्षिप्त नाम टीवीई शिक्षा के सभी रूपों और स्तरों को संदर्भित करता है जो स्कूल-आधारित और कार्य-आधारित दोनों संदर्भों में औपचारिक , गैर-औपचारिक और अनौपचारिक सीखने के तरीकों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिएव्यावसायिक विद्यालय एक प्रकार का शैक्षणिक संस्थान है जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- भारत में विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, जिसे शिक्षित करके अर्थव्यवस्था के लिये उपयोगी बनाना कठिन कार्य है। कोविड-19 के कारण सभी को शिक्षा मुहैया कराना तथा कौशल विकास सम्बंधी कार्यों का प्रशिक्षण देना और भी चुनौतीपूर्ण है।

- एक सर्वेक्षण के अनुसार नई नौकरियों में विश्वविद्यालयों के स्नातकों की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी अधिक भुगतान प्राप्त करने में सक्षम हैं। साथ ही, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को नौकरी प्राप्त करने में भी अपेक्षाकृत कम समय लगता है।

2. समस्याएँ

- भारत में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दी जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास की तुलना में पुस्तकीय ज्ञान और लिखित परीक्षाओं पर अधिक केंद्रित है।

- एक तरफ जहाँ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की सर्वसुलभता नहीं है, वहीं तकनीकी और कौशल विकास से सम्बंधित कार्यक्रम केवल शहरी आबादी तक ही सीमित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुँच नगण्य है।

- भारत में कौशल विकास के तहत आने वाले बढ़ई तथा दर्जी जैसे पेशों को लेकर लोगों में कम रुची देखी गई है। साथ ही, इन कार्यों को सामाजिक रूप से निम्न कोटि का माना जाना भी एक चुनौती है।

3. सुझाव और सिफ़ारिशें

निजी टीवीईटी प्रदाताओं में लाभ कमाने वाली और गैर-लाभकारी संस्थाएँ शामिल हैं। कई कारकों ने निजी टीवीईटी के विस्तार का समर्थन करने के लिए कार्रवाई शुरू की, जिसमें सार्वजनिक टीवीईटी प्रदाताओं की सीमित क्षमताएँ और उद्यमों और प्रशिक्षुओं के प्रति उनकी कम प्रतिक्रिया शामिल है। निजी टीवीईटी प्रदाताओं से अधिक उत्तरदायी होने की उम्मीद थी क्योंकि वे सार्वजनिक संस्थानों (विशेष रूप से केंद्रीकृत प्रणालियों में) की तुलना में कम नौकरशाही प्रतिबंधों के अधीन थे। उनकी उपस्थिति से सिस्टम-वाइड गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद थी, कई विकासशील देशों में, सरकारी बजट टीवीईटी के लिए वित्तपोषण का एक कमजोर और अविश्वसनीय स्रोत था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नियोक्ताओं और प्रशिक्षुओं सहित लाभार्थियों के योगदान को बढ़ाकर टीवीईटी प्रणालियों को वित्तपोषित करना था।

2005 से निजी टीवीईटी प्रावधान उप-सहारा अफ्रीका , मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में टीवीईटी का एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है । कुछ देशों में, जैसे लेबनान , निजी टीवीईटी संस्थानों में नामांकन सार्वजनिक संस्थानों में नामांकन से अधिक है। जॉर्डन में , सामुदायिक कॉलेज स्तर पर निजी प्रावधान को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है। हालांकि, निजी स्वामित्व वाले संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों के साथ सभी अनुभव सकारात्मक नहीं रहे हैं , उनके पाठ्यक्रम अक्सर पेशेवर क्षेत्रों में केंद्रित रहे हैं जिनमें आमतौर पर बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे निजी प्रदाताओं द्वारा इस क्षेत्र में आसान प्रवेश और निकास की अनुमति मिलती है। गुणवत्ता के मुद्दे भी सामने आए हैं, जहां गुणवत्ता के बारे में बाजार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

4. तकनीकी उन्नति और उसका प्रभाव

ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रसार में TVET की महत्वपूर्ण भूमिका है। तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति का TVET पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा। उत्तरदायी TVET सिस्टम और अधिक व्यापक रूप से प्रभावी कौशल नीतियों को डिजाइन करने के लिए परिवर्तनों को समझना और उनका पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में तेजी से और कुछ मामलों में मौलिक रूप से बदलती जरूरतों के लिए कौशल की आपूर्ति को अनुकूलित करने की लचीलापन TVET सिस्टम की एक केंद्रीय विशेषता बन गई है। वैश्विक स्तर पर, नौकरी में प्रवेश के लिए कौशल की आवश्यकता और योग्यता बढ़ रही है। यह न केवल अधिक जानकार और कुशल कार्यबल की आवश्यकता को दर्शाता है, बल्कि एक ऐसे कार्यबल की भी आवश्यकता है जो निरंतर सीखने के चक्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ जल्दी से अनुकूलन कर सके।

TVET पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की विविध ICT आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वे काम, शिक्षा या नागरिकता से संबंधित हों। ICT नौकरी बाजार में व्यावसायिक परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जबकि कई TVET प्रदाताओं ने प्रावधान को एक मिश्रित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिसमें काफी अधिक स्व-निर्देशित और/या दूरस्थ शिक्षा शामिल है। विकसित देशों में, TVET संगठनों को आधुनिक बनाने और शिक्षार्थी रिकॉर्ड सहित प्रशासन और वित्त का प्रबंधन करने के लिए नए ICT दृष्टिकोण पेश किए गए हैं।

5. श्रम बाजार की मांग और चुनौतियां

2008 के वित्तीय संकट के बाद , दुनिया भर के श्रम बाजारों में संरचनात्मक परिवर्तन हुए, जिसने कौशल और टीवीईटी की मांग को प्रभावित किया। बेरोजगारी बढ़ी और नौकरियों की गुणवत्ता में कमी आई, खासकर युवाओं के लिए । श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर ने पुरुषों को महिलाओं से आगे रखा और कौशल बेमेल गहरा गया। संकट ने श्रम बाजारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और अनिश्चितता, रोजगार की भेद्यता और असमानता को गहरा किया। इसके अलावा, आर्थिक सुधार में दक्षता और लाभप्रदता में सुधार के उपायों ने अक्सर बेरोज़गारी विकास को जन्म दिया है , जैसा कि अल्जीरिया , भारत और रंगभेद के बाद के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ।

असुरक्षित रोजगार के स्तर को संबोधित करने की कोशिश में, टीवीईटी प्रणालियों ने स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और मौजूदा असुरक्षित श्रम बाजारों में प्रभावी ढंग से काम करने और अन्य श्रम बाजार बाधाओं को समायोजित करने

की उनकी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका मतलब है टीवीईटी और रोजगार नीतियों के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय। इसने टीवीईटी प्रणालियों के लिए ऐसे तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता पैदा की है जो कौशल की जरूरतों को जल्दी पहचान सकें और कौशल की मांग और आपूर्ति के मिलान के लिए श्रम बाजार की जानकारी का बेहतर उपयोग कर सकें। टीवीईटी प्रणालियों ने तत्काल नौकरी कौशल और व्यापक दक्षताओं को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यह निर्देश और कार्यस्थल सीखने के लिए योग्यता-आधारित दृष्टिकोणों को अपनाकर पूरा किया गया है जो शिक्षार्थियों को असुरक्षित रोजगार को संभालने, बदलती नौकरियों और करियर के संदर्भों को समायोजित करने और सीखने की क्षमता और अनुकूलन के लिए चपलता का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।

6. विशेषज्ञ कौशल के साथ-साथ व्यापक दक्षता प्रदान करना

आर्थिक विकास के लिए कौशल में तकनीकी और सॉफ्ट कौशल का मिश्रण शामिल है । यूनेस्को द्वारा किए गए अनुभवजन्य साक्ष्य और टीवीईटी नीति समीक्षा से पता चलता है कि टीवीईटी सिस्टम अभी तक तथाकथित सॉफ्ट दक्षताओं के विकास का पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं कर सकते हैं। हालांकि, कई देशों ने टीवीईटी पाठ्यक्रम में सुधार के उपायों के रूप में योग्यता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है।

जमैका की हार्ट ट्रस्ट नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें योग्यता मानकों और संतुलित नौकरी-विशिष्ट और सामान्य कौशल पर विशेष जोर दिया गया। योग्यता मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रशिक्षण उद्योग से जुड़ा हुआ था और अद्यतित था, और आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ-साथ योग्यताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया था। कौशल प्रकारों का संतुलन यह सुनिश्चित करने के लिए था कि नौकरी-विशिष्ट कौशल के साथ-साथ वैचारिक और अनुभवात्मक ज्ञान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए ताकि व्यक्तियों को कार्यस्थल में और अधिक सामान्य रूप से समाज में विकसित और विकसित होने में सक्षम बनाया जा सके।

7. सामाजिक समानता और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देना

युवाओं और वयस्कों के हाशिए पर पड़े समूहों को सही कौशल के साथ तैयार करना और उन्हें स्कूल से काम पर जाने में मदद करना सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में TVET के सामने आने वाली समस्या का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल समावेशी है, समावेशन और बहिष्कार की प्रासंगिक गतिशीलता और व्यक्तियों की क्षमताओं के आधार पर कई नीतिगत चुनौतियों का सामना करता है। उदाहरण के लिए, विकलांग लोगों और वंचित महिलाओं द्वारा बहिष्कार के अनुभव कुछ मायनों में समान और अन्य में अलग हो सकते हैं। कई व्यक्ति कार्यस्थल में विभिन्न प्रकार के नुकसान का अनुभव करते हैं, जो किसी विशिष्ट संदर्भ या संगठन में सामाजिक दृष्टिकोण और परंपराओं के आधार पर अलग-अलग गंभीरता के होते हैं। इसलिए कार्यस्थल में समावेशिता के दृष्टिकोण जनसंख्या की जरूरतों, सामाजिक विविधता और संदर्भ के अनुसार अलग-अलग होंगे। एक उदाहरण देने के लिए, नीदरलैंड ने भाषा निर्देश को काम के साथ जोड़ने वाले कार्यक्रम और कुछ मामलों में नौकरी पर प्रशिक्षण देकर कम कुशल वयस्कों के लिए कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाने का कार्य शुरू किया।

8. उपसंहार

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐतिहासिक रूप से श्रम मंत्रालय , अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों द्वारा संभाला जाने वाला विषय रहा है । मानकों और लागतों के संदर्भ में विविधताओं और बहुलता को सुसंगत बनाने के लिए, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा दिसंबर 2013 में शुरू की गई थी।

छात्रों को काम के बारे में जागरूक करने के लिए प्राथमिक मानकों (ग्रेड 1-8) में कार्य शिक्षा को शामिल किया गया है। निचले माध्यमिक स्तर (ग्रेड 9-10) में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की कार्य की दुनिया से परिचितता बढ़ाना है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) एक योग्यता-आधारित रूपरेखा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं को व्यवस्थित करती है। एक से दस तक वर्गीकृत इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो शिक्षार्थी के पास होने चाहिए, चाहे वे औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। भारत में NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी NVEQF (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता रूपरेखा) सहित अन्य सभी रूपरेखाएँ NSQF द्वारा प्रतिस्थापित हैं। [

नवंबर 2014 में भारत में नई सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया । इस तरह के मंत्रालय की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, "एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, जो उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने का काम देखेगा। यहां तक कि विकसित देशों ने भी कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है"।

देश भर में कौशल विकास गतिविधियों को सुसंगत और समेकित करने के अपने प्रयासों की निरंतरता के रूप में, सरकार ने 15 जुलाई 2015 को पहला कौशल भारत विकास मिशन (एनएसडीएम) लॉन्च किया। इस दिन राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति भी लॉन्च की गई।

आज सरकार (प्रशिक्षण महानिदेशालय) और सार्वजनिक निजी भागीदारी शाखा (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के माध्यम से सभी कौशल विकास प्रयास कौशल भारत मिशन के माध्यम से मंत्रालय के अधीन किए जाते हैं|

मंत्रालय पूर्ण अभिसरण के लिए पांच साल की कार्यान्वयन अनुसूची के आधार पर सभी सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में एनएसक्यूएफ को लागू करने में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकार के साथ काम करता है।

कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने पहुंच, गुणवत्ता और अभिनव वित्तपोषण मॉडल को बढ़ाया है, जिससे जमीनी स्तर पर स्थायी कौशल विकास संगठनों का निर्माण हुआ है। अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रम (ज्यादातर निजी संगठनों द्वारा पेश किए जाते हैं) भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईटीआई) द्वारा पेश किए जाने वाले दीर्घकालिक कार्यक्रमों के साथ मिलकर बड़े ढांचे के तहत एक दूसरे के पूरक हैं। क्रेडिट समतुल्यता, अंतरराष्ट्रीय मानक, गुणवत्ता आश्वासन और मानकों का प्रबंधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (मंत्रालय

के तहत एक स्वायत्त निकाय) के माध्यम से उद्योग-नेतृत्व वाले क्षेत्र-विशिष्ट निकायों (सेक्टर स्किल काउंसिल) और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में किया जा रहा है।

भारत ने वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानकों को लागू करने और भारतीय कार्यबल को विदेशों में नौकरी की गतिशीलता प्रदान करने के इरादे से यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और यूएई की सरकारों के साथ द्विपक्षीय सहयोग किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. यूनेस्को (2011)। इक्कीसवीं सदी के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित संशोधित अनुशंसा |
2. नजेंगा, मूसा (2020)। "टीवीईटी की एक व्यावहारिक संकल्पना"। सेसेहने में, पप्प इमोला; क्रेसिने, स्ज़ोकोली मारिया (संस्करण)। फ़ेलनॉटकोरी टैनुलास: फ़ोकसज़बान ए स्ज़ाकेपज़ेस एक मंकेरोपियाक है (वयस्क शिक्षा: व्यावसायिक प्रशिक्षण और श्रम बाजार पर ध्यान दें) |
3. किआदो (2024)। कौशल विकास के लिए सरकार का पूरा दृष्टिकोण अपनाना । यूनेस्को। आईएसबीएन 978-92-3-100282-3 मूल से 2020-08-08 को संग्रहीत |
4. बिललेट, स्टीफन (2022)। व्यावसायिक शिक्षा: उद्देश्य, परंपराएँ और संभावनाएँ। ड्रोड्रेच्ट: स्प्रिंगर। आईएसबीएन 9789400719538.
5. मैकलीन, रूपर्ट; हर्शबैक, डेनिस आर, एड. (2009).कार्य के बदलते शब्द के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तिका.doi:10.1007/978-1-4020-5281-1.आईएसबीएन 978-1-4020-5280-4.
6. मैकग्राथ, साइमन (2021)। "अफ्रीका में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अब कहाँ जाना है"। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। 9 (1):35–48. doi:10.5172/ijtr.9.1-2.35.S2CID145050191.
7. पोरेस, गिसेले टूर; वाइल्डमेर्श, डैनी; सिमंस, मार्टेन (2014)। "व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रथाओं की मुक्ति क्षमता पर विचार: संवाद में फ़ेयर और रैनसीयर"। सतत शिक्षा में अध्ययन । (3): 275–289 . doi : 10.1080/0158037X.2014.904783 । S2CID 143863632 ।
8. होएकेल, कैथरीन (2023). "व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की लागत और लाभ" (पीडीएफ) .
9. वर्ट्ज़, मारियाना (2024). "शिक्षा और चरित्र: विल्हेम वॉन हम्बोल्ट का शास्त्रीय पाठ्यक्रम"। वाशिंगटन, डीसी: शिलर इंस्टीट्यूट। मूल से 2018-06-29 को संग्रहीत ।
10. निदा-रुमेलिन, जूलियन (29 अक्टूबर 2024)। "बोलोग्ना-प्रोजेस: डाई चांस ज़म कॉम्प्रोमिस इस्ट दा" । डाई ज़िट (जर्मन में)। 20 फरवरी 2016 को मूल से संग्रहीत 29 नवंबर 2025 को लिया गया .
11. मैकलीन, आर. और पावलोवा, एम. 2021. माध्यमिक और उच्च शिक्षा का व्यावसायिकीकरण: कार्य की दुनिया के लिए मार्ग।
12. यूनेस्को-यूएनईवीओसी, टीवीईटी में वैश्विक रुझानों पर पुनर्विचार: सिद्धांत और व्यवहार पर विचार । बॉन, जर्मनी, यूनेस्को-यूएनईवीओसी अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र, पृष्ठ 40-85 ।